



2026:AHC:66995-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 11030 वर्ष 2026

धीरचंद्र शर्मा और 3 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: प्रमोद कुमार सिंह पालीवाल

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुनील कुमार सिंह

न्यायालय सं - 21

माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चंद्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति श्री कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार सिंह पालीवाल, राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्री आदित्य भूषण सिंघल, प्रतिपक्षी के अधिवक्ता - यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) और श्री सुनील कुमार सिंह, प्रतिपक्षी के अधिवक्ता - ग्राम सभा ऊंची दनकौर, तहसील सदर, जिला गौतम बुद्ध नगर को सुना।
2. प्रस्तुत रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करते हुए दायर की गई है:

"i) परमादेश आदेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना और प्रतिपक्षियों को उनकी भूमिधारी भूमि अराजी संख्या-141 पर याचिकाकर्ता का नाम दर्ज करने का निर्देश देना, जिसे लेखपाल (अनुलग्नक संख्या-7) द्वारा रिपोर्ट किया गया था;

ii) इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर दिनांक 09.02.2024 और 24.09.2023(रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या-8 और 9)



के लंबित अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए आयुक्त, मेरठ डिवीजन, मेरठ को परमादेश आदेश और निर्देश देने की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना;

iii) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित समझे।

iv) याचिकाकर्ता के पक्ष में रिट याचिका की लागत का पंचाट करें।

3. शुरुआत में, प्रतिपक्षियों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ताओं ने इस आधार पर प्रस्तुत रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में आपत्ति जताई है कि यदि याचिकाकर्ता इस तथ्य से व्यथित हैं कि भले ही वे विचाराधीन भूखंड के जोत धारक हैं, यानी अराजी संख्या-141, और यदि, एक गलत अनुमान पर, राजस्व अधिकारियों ने उक्त भूमि को ग्राम सभा से संबंधित माना है, तो इस तरह की विसंगति को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 32 (इसके बाद 'कोड, 2006' के रूप में संदर्भित) या उत्तर प्रदेश होल्डिंग्स समेकन नियम, 1954 के नियम 109ए के तहत (इसके बाद 'नियम, 1954' के रूप में संदर्भित) के तहत ठीक किया जा सकता है, जो राजस्व अभिलेखों में सुधार की प्रक्रिया प्रदान करता है, और याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध उचित उपाय कलेक्टर/चकबंदी अधिकारी से संपर्क करना है। इस पृष्ठभूमि में, प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तत्काल कार्यवाही गलत है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के बराबर है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत को कानून के अनुसार संहिता, 2006 या नियम, 1954 के प्रावधानों के तहत उचित रूप से दबाया जा सकता है, और उक्त वैधानिक उपाय का लाभ उठाने के बजाय, याचिकाकर्ताओं ने अपनी शिकायत के निवारण के लिए सीधे इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करते हुए और प्रस्तुत रिट याचिका में मांगी गई राहतों के अवलोकन पर, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा आंदोलन की गई शिकायत मुख्य रूप से संबंधित भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेखों में उनके नाम सुधारने/दर्ज करने से संबंधित है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश प्रदेश राजस्व संहिता, 2006/नियम, 1954 के प्रावधानों के तहत एक प्रभावी वैधानिक उपाय उपलब्ध है। चूंकि इस मामले में राजस्व प्रविष्टियों और शीर्षक/कार्यकाल अधिकारों



से संबंधित विवादित प्रश्नों का निर्णय शामिल है, इसलिए यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, इस स्तर पर गुण-दोष के आधार पर इसकी जांच करने के लिए इच्छुक नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के दावे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह प्रावधान किया गया है कि याचिकाकर्ता संहिता, 2006/नियम, 1954 के तहत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उचित वैधानिक उपाय का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे, और यदि ऐसी कार्यवाही शुरू की जाती है, तो उस पर विचार किया जाएगा और कानून के अनुसार सख्ती से निर्णय लिया जाएगा।

5. रिट याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

31 मार्च 2026 एनएलवाई

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह)

(न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)